भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 651
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2020

निःशुल्क वाई-फाई

651. श्री दयाकर पसुनूरी; श्री एन° रेड्डप्पः
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में 48,000 गांवों को निःशुल्क वाई-फाई प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा भारतनेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/व्यय की गई है; और
(घ) इस संबंध में विभिन्न राज्यों की दृष्टिकोणों एवं उनकी मांगों को किस हद तक पूरा किया गया है?

उत्तर
संचार, मानव संसाधन विकास तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख): देश की लगभग सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारतनेट परियोजना का चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारतनेट परियोजना के भाग के रूप में, सभी ग्राम पंचायतों में अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी, वाई-फाई या अन्य किसी उचित ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी है।

भारतनेट चरण-I की लगभग 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में, वाई-फाई सेवाएं आदि उपलब्ध कराने का दायित्व राजस्थान सरकार, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिस इंडिया लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विशेष प्रयोजन साधन) को सौपा गया है। भारतनेट चरण-II की 1407 ग्राम पंचायतों में, वाई-फाई सेवाओं के साथ-साथ सैटेलाइट मीडिया पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का दायित्व बीएसएनएल को सौंपा गया है।

आज की स्थिति के अनुसार 45,769 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट की संस्थापना की गई है और उनमें से 18,041 ग्राम पंचायतों में सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा, व्यवहार्यता अंतर पोषण (वीजीएफ) के जरिए अंतिम छोर तक की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जानी है, तथापि, सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिस इंडिया लिमिटेड द्वारा भारतनेट नेटवर्क के माध्यम से वाई-फाई सेवाएं मार्च 2020 तक निःशुल्क मुहैया कराई जाएंगी।

(ख) और (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत/खर्च की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। निधियों का संवितरण कार्यान्वयन करार ऐजेंसियों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों/ समझौता-ज्ञापन (एमओयू) में दर्शाए गए लक्ष्यों को हासिल करने के बाद ही किया जाता है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 05.02.2020 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 651 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उललिखित अनुबंध

ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ावे के लिए किए संवितरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	**राज्य/संघ क्षेत्र**	**संवितरण/व्यय (करोड़ में)**
1	अंडमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	7.05
3	असम	7.79
4	बिहार	33.21
5	छत्तीसगढ़	25.83
6	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.19
7	गुजरात	26.62
8	हरियाणा	30.2
9	हिमाचल प्रदेश	50.94
10	जम्मू और कश्मीर	1.49
11	झारखंड	17.21
12	कर्नाटक	22.13
13	केरल	5.42
14	मध्य प्रदेश	81.95
15	महाराष्ट्र	75.2
16	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा)	3.39
क्र.सं.	**राज्य/संघ क्षेत्र**	**संवितरण/व्यय (करोड़ में)**
17	पूर्वोत्तर-II (अरूणाचल प्रदेश, मणीपुर और नागालैंड)	2.44
18	ओडीशा	18.77

19	पुडुचेरी	1.77
20	पंजाब	38.54
21	राजस्थान	47.2
22	सिक्किम	0.08
23	तेलंगाना	9.83
24	तमिलनाडु	0
25	उत्तर प्रदेश	324.47
26	उत्तराखंड	12.91
27	पश्चिम बंगाल	10.33
कुल योग		**854.96**
टिप्पणी: उपरोक्त के अतिरिक्त, बीबीएनएल द्वारा छ: माह के लिए भारतनेट चरण-I की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को 999/- रू. प्रतिमाह का एक प्लान का वित्तपोषण किया गया है।		

******